Date - 9 Feb 2022

राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- "पर्वतमाला"

- हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- "पर्वतमाला" की घोषणा की है।

पर्वतमाला योजना के बारे में:

- योजना पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड में शुरू की जाएगी, जो कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए पारिस्थितिक रूप से स्थायी विकल्प होगी।
- यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार से संबंधित है।
- इसमें वे भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जहां पारंपरिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था संभव नहीं है।
- यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है।
- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2022-23 में 60 किमी. लंबाई के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।

नोडल मंत्रालय:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पास क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ-साथ निर्माण, अनुसंधान और नीति विकास की जिम्मेदारी होगी।
- भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 को फरवरी 2021 में संशोधित किया गया, जिसने MORTH को रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधानों के विकास की देखभाल करने में सक्षम बनाया।

Yojna IAS

- यह कदम एक नियामक व्यवस्था स्थापित करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा।
- 'MORTH' अब तक देश भर में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार रहा है।

महत्त्व:

परिवहन का किफायती तरीका:

- यह ध्यान में रखते हुए कि रोपवे परियोजनाएं पहाड़ी इलाकों में एक सीधी रेखा में बनाई गई हैं, इससे भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम हो जाती है।
- अत: रोडवेज की तुलना में प्रति किमी. निर्माण की उच्च लागत के बावजूद, रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत रोडवेज की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है।

परिवहन का तेज़ तरीका:

- रोपवे परिवहन के हवाई मार्ग के कारण सड़क परियोजनाओं की तुलना में काफी फायदेमंद है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रोपवे का निर्माण एक सीधी रेखा में किया जा सकता है।

पर्यावरण के अनुकूल:

- इसमें कम धूल उत्सर्जन होता है। संबंधित सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि पर्यावरण में किसी भी तरह के संदूषण से बचा जा सके।

पूर्ण कनेक्टिविटी:

- '3S' (एक विशिष्ट प्रकार की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएं प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों को परिवहन कर सकती हैं।

चुनौतीपूर्ण / संवेदनशील इलाके के लिए आदर्श:

- लंबी रस्सी की अवधि: इस प्रणाली में नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों जैसी बाधाओं को बिना किसी समस्या के पार किया जा सकता है।
- टावरों पर गाइडेड रस्सियाँ: कम जगह की आवश्यकता होती है और मनुष्यों या जानवरों के लिए कोई अवरोध नहीं होता है।

अर्थव्यवस्था:

- रोपवे में सिंगल पावर प्लांट और ड्राइव मैकेनिज्म द्वारा संचालित कई केबल कार शामिल हैं।
- यह निर्माण और रखरखाव दोनों की लागत को कम करता है।
- रोपवे में सिंगल ऑपरेटर के इस्तेमाल से श्रम लागत में कमी आएगी।

Yojna IAS

- समतल भूमि पर रोपवे की लागत नैरो-गेज रेलमार्ग के साथ प्रतिस्पर्धी है, जबकि रोपवे पहाड़ों में कहीं बेहतर है।

लचीला:

- विभिन्न सामग्रियों का परिवहन- एक रोपवे एक साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का परिवहन कर सकता है।

बड़ी ढलानों को संभालने की क्षमता:

- रोपवे और केबल-वे (केबल क्रेन) बड़े ढलान और ऊंचाई में बड़े अंतर को संभाल सकते हैं।
- जहां सड़क या रेलमार्ग के लिए स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन की यात्रा करता है। इंग्लैंड में ओल्ड क्लिफ रेलवे और पहाड़ों में स्की रिसॉर्ट रोपवे इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

कम भूमि की आवश्यकता:

- तथ्य यह है कि अंतराल पर केवल संकीर्ण आधार ऊर्ध्वाधर समर्थन की आवश्यकता होती है, शेष भूमि को मुक्त छोड़कर, निर्मित क्षेत्रों में और उन स्थानों पर जहां भूमि उपयोग के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, रोपवे बनाना संभव बनाता है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

- गर्मियों की शुरुआत के साथ, वन्यजीवों का मौसमी प्रवास कर्नाटक और तमिलनाडु में आसपास के वन्यजीव अभयारण्यों से केरल में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (डब्ल्यूडब्ल्यूएस) की ओर शुरू हो गया है।
- वर्ष भर चारे और पानी की आसान उपलब्धता के कारण, यह अभयारण्य गर्मियों के दौरान वन्यजीवों का पसंदीदा आश्रय स्थल है।

वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है?

- केरल में स्थित वायनाड वन्यजीव अभयारण्य (WWS) नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी।
- नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क (2012 में नामित) में शामिल किया गया था।
- इस रिजर्व के तहत अन्य वन्यजीव पार्कों में मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल हैं।
- 44 वर्ग कि.मी. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, 76 के क्षेत्र में फैला है, कर्नाटक में नागरहोल और बांदीपुर और तमिलनाडु में मुदुमलाई के बाघ अभयारण्यों से सटा हुआ है।
- काबिनी नदी (कावेरी नदी की एक सहायक नदी) इस अभयारण्य से होकर बहती है।

Yojna IAS

- यहां पाए जाने वाले वन प्रकारों में दक्षिण भारतीय नम पर्णपाती वन, पश्चिमी तटीय अर्ध-सदाबहार वन और सागौन, नीलगिरी और ग्रेवेलिया के वन शामिल हैं।
- हाथी, गौर, बाघ, चीता, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली सूअर, सुस्त भालू, नीलगिरि लंगूर, बोनट मैकाक, लंगूर, मालाबार विशालकाय गिलहरी आदि प्रमुख स्तनधारी यहां पाए जाते हैं।

ऑपरेशन आहट

- रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू की है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही हैं।
- यह ऑपरेशन रेल मंत्रालय के तहत किया जा रहा है, आरपीएफ रेल मंत्रालय के तहत काम करता है।

ऑपरेशन आहट:

- इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों में स्पेशल फोर्स तैनात करेगी, ऑपरेशन मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने पर केंद्रित होगा।
- यह ऑपरेशन भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जाएगा। भारतीय रेलवे कुल 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है। आरपीएफ के अनुसार तस्करों के लिए रेलवे परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है।
- इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ सुराग इकट्ठा करेगा, मिलान करेगा और उसका विश्लेषण करेगा। मार्गों, पीड़ितों, स्रोतों, गंतव्य और लोकप्रिय ट्रेनों की जानकारी एकत्र की जाएगी।
- आरपीएफ ऑपरेशन में अपनी सारी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करेगी। एकत्र किए गए विवरण को अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। आरपीएफ स्थानीय पुलिस की मदद करेगा और अंतर्राज्यीय कार्यों में सेतु का काम करेगा।
- इस ऑपरेशन के तहत साइबर सेल बनाए जाएंगे। म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- आरपीएफ ने 2017 से 2021 के बीच दो हजार महिलाओं को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया।
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर साल 2,200 नए तस्करी के मामले दर्ज किए जाते हैं।
- 2011 में, भारत सरकार ने UNTOC की पुष्टि की। UNTOC का मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यूएनटीओसी प्रोटोकॉल मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और सजा को कवर करता है।

ऑपरेशन की आवश्यकता क्यों?

- महिलाएं और बच्चे यौन शोषण, घरेलू गुलामी और जबरन शादी के लिए मानव तस्करी के मुख्य शिकार हैं।

Yojna IAS

- इसके अलावा, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की दासता आदि के लिए मानव तस्करी भी होती है।
- अवैध व्यापार किए गए लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। सर्कस में काम करने, भीख मांगने, अवैध गोद लेने, मनोरंजन उद्योग में काम करने आदि के लिए भी उनकी तस्करी की जाती है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS